C M Y K

रायगढ़ , गुरूवार
01.03.2018
मघा 11.10 रात, शुक्रवार
होलिका दहन
पृष्ठ 8, मूल्य 3

साप्ताहिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

Happy Holi

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि **न्यायसाक्षी** जल्द दैनिक हो रहा है। अपनी प्रति सुरक्षित कराए, सभी सम्मानीय पाठकों को होली की बधाईयाँ। // **कृते सम्पादक** //

Web: www.nyaysakshi.com

3 में देखें... संकट में सरकारी बैंक ... 6 में देखें मनोरंजन के साथ विशेष ....

» वर्ष-2 » अंक - 8 »

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

गांधी रेलवे स्टेशन बना देश का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन

जयपुर ,(आरएनएस)। जयपुर का गांधी नगर रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। टिकट बेचने से लेकर टिकट की चेकिंग तक सभी कार्य यहां 40 महिलाओं द्वारा संचालित किये जायेंगे। कुल 40 महिलाओं में से 4 ट्रेन संचालन का काम देखेंगी, 8 टिकट की बुकिंग का काम देखेंगी और 6 आरक्षण का काम देखेंगी, अन्य 6 टिकट चेकिंग का काम और अनाउंस करने का काम देखेंगी। अन्य 10 आरपीएफ को देखेंगी जबकि अंतिम 6 महिलाएं अन्य छोटे-मोटे काम देखेंगी। जानकारी के मुताबिक, सभी कर्मचारी 8 घंटे के ट्यूटी आवर में तीन शिफ्ट में काम करेंगे। नीलम जाटव गांधी नगर रेलवे स्टेशन की पहली स्टेशन सुपरिटेंडेंट होंगी। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर सभी महिला स्टाफ रखने की योजना एनडब्ल्यूआर के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा बनाया गया जबकि विभागीय रेलवे प्रबंधक और अन्य रेलवे अधिकारियों ने मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन किया है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने भी स्टेशन पर जीआरपी और लेडी पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर इस काम में सहयोग दे रही है।

उत्तरप्रदेश में बीजेपी के कार्यकाल में दिखने लगा है विकास

लखनऊ ,(**आरएनएस**)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रदेश के अंदर डेढ़ दशक से चली आ रही परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की नीति की सरकारों के विपरीत भाजपा के 11 माह के कार्यकाल में ही एक बीमार राज्य में अब विकास दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज यहां मुमुक्षु शिक्षा संस्थान के युवा महोत्सव के समापन के अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस उन्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए जैसे भगवान राम ने युवावस्था में अपनी ऊर्जा का प्रयोग मानवता के लिए किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जोड़ रहे हैं, वह हर चेहरे पर खुशहाली, गरीबी मुक्त भारत, आतंकवाद, परिवारवाद से मुक्त एक ऐसा भारत बना रहे हैं जिससे हर नागरिक को बिजली, रसोई गैस, रोटी-पानी आसानी से मिल सके। योगी ने कहा कि उन्होंने 2 माह में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने का काम किया है। यहां कोई निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि यहां जंगलराज था, भाई-भतीजावाद था, कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने सबसे पहले कानून का राज कायम किया, निवेशकों को बेहतर माहौल दिया इसके बाद इन्वेस्टर्स समिट कराया। इससे 35 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प उत्पादक को बढ़ावा देना तथा 3 वर्ष में 20 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ दिया जाएगा तथा प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाओं को प्रदेश के साथ जोड़कर कई गुना रोजगार युवाओं को मिलेगा। योगी ने कहा कि हम पत्रकारों के लिए भी एक नई आवासीय योजना की शीघ्र ही घोषणा करेंगे।

नीरव और माल्याओं पर शिकंजे के लिए नये कानून की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली (**आरएनएस**)। देश के बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून के तहत आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि वे कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो जाते। फिलहाल यह बिल पब्लिक डोमेन में है और इस पर लोगों से राय ली जा रही है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक भगोड़ा आर्थिक अपराधी का अर्थ उस व्यक्ति से होगा, जिसके खिलाफ आर्थिक अपराध में अरेस्ट वॉरंट जारी हुआ हो और उसने कानूनी शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़ दिया हो। प्रस्तावित विधेयक को यदि मंजूरी मिल जाती है तो आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए बने अन्य कानूनों की यह जगह ले लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विधेयक 6 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया, यह आमतौर पर महसूस किया जा रहा है कि देश की कानूनी प्रक्रिया से बचकर आर्थिक अपराधियों का विदेश भाग जाना, भारत के कानून को कमतर आंकने जैसा है।

प्रस्ताव फेल होने के डर से चीन ने भी छोड़ा पाकिस्तान का साथ

इस्लामाबाद ,(**आरएनएस**)। फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के ऐक्शन के खिलाफ अब पाकिस्तान को चीन का साथ भी नहीं मिल पाएगा। टेरर फाइनैंसिंग को रोकने में असफल होने के बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। एफएटीएफ के इस कदम को रोकने के लिए तीन देशों के समर्थन वाले एक नए प्रस्ताव को रोकने की जरूरत है। पाकिस्तान को अबतक चीन, सऊदी अरब और तुर्की का समर्थन था। सऊदी ने पहले ही अपने कदम वापस खींच लिए थे और चीन भी अब पीछे हट गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को इस बात की सूचना दे दी है कि अब वह इस मामले से बाहर रहने वाला है। चीन ने कहा है कि असफल होने वाले प्रस्ताव को अपना समर्थन देकर वह अपनी स्थिति को कमजोर नहीं बना सकता। ऐसे में पाकिस्तान की इकॉनमी के ब्लैकलिस्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। अगर जून तक पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग को खत्म करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना नहीं तैयार की तो ब्लैकलिस्ट में शामिल देशों में शुमार कर लिया जाएगा। 37 देशों वाले फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पिछले हफ्ते पैरिस में फुल मेंबर बैठक की थी। इसमें पाकिस्तान को ऐसे देशों की वॉचलिस्ट में शामिल किया था जहां आतंकी संगठन अभी भी फंड इकट्ठा करने में जुटे हैं। शुक्रवार को ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियों वाले देश के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का समर्थन भी था। हालांकि 20 फरवरी को बैठक में चीन, सऊदी अरब और तुर्की ने मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। गौरतलब है कि सऊदी अरब एफएटीएफ का फुल मेंबर नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने अभूतपूर्व रूप से पाकिस्तान पर दूसरी बार चर्चा का प्रस्ताव ला दिया। इस दौरान अमेरिका ने फुल मेंबरशिप दिलाने की बात कर सऊदी अरब को अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान के खेमे में केवल दो देश, चीन और तुर्की ही रह गए। एफएटीएफ में किसी भी नए कदम को रोकने के लिए कम से कम 3 सदस्य देशों का समर्थन होना चाहिए। ऐसे में चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ एक बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान की इकॉनमी पर पड़ेगा विपरीत प्रभाव फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स की ओर से पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने से उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। टास्क फोर्स के इस कदम के बाद अब पाकिस्तान के सामने अन्य एजेंसियों की ओर से भी डाउनग्रेड किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। आगे अगर पाक के रवैये में सुधार नहीं हुआ तो उसकी इकॉनमी ब्लैकवलिस्ट भी हो सकती है। पाकिस्तान की इकॉनमी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डिवेलपमेंट बैंक समेत मूडीज, स्टैंडर्ड ऐंड पूअर और फिच जैसी एजेंसियां पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर सकती हैं। ऐसा होने पर पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट समेत पूरी इकॉनमी में गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। इससे सीधे तौर पर चीन को फायदा होगा और उसके सामने पाकिस्तान में निवेश के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान सरकार के आंतरिक सूत्र ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया, ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि पाकिस्तान के लिए इंटरनैशनल मार्केट से फंड हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खाकन अब्बासी के आर्थिक सलाहकार मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया कि इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति के प्रस्ताव की लोगों ने की निंदा

पेइचिंग, (**आरएनएस**)। राष्ट्रपति शी चिनफिंग को अनिश्चित काल तक के लिए राष्ट्रपति बनाए रखने के चीन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव को कड़ी प्रति क्रिया का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती देख चीन चकरा गया और बिना देर किए उसने कमान संभाल ली। देखते ही देखते चीन ने व्यापक तौर पर प्रचार शुरू किया। इसके तहत चीन ने कुछ लेखों को ब्लॉक कर दिया और ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिनमें पार्टी और शि चिनफिंग की बढ़-चढ़कर तारीफ की गई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी ने संविधान के उस प्रावधान में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लगातार दो कार्यकाल तक ही बने रहने की बात कही गई है। अगर यह फेरबदल होता है कि शी चिनफिंग अनिश्चित काल तक के लिए चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। गौरतलब है कि संविधान में शी चिनफिंग के राजनीतिक विचारों को भी जोड़ा जाएगा, जो पार्टी के संविधान में पहले ही जोड़े जा चुके हैं। इससे न सिर्फ एक भ्रष्टाचार विरोधी कानूनी ढांचा तैयार होगा, बल्कि सत्ता पर पार्टी की पकड़ भी मजबूत बनेगी। हालांकि लग रहा है कि पार्टी को चीन में अभी भी कुछ लोगों को मनाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी।

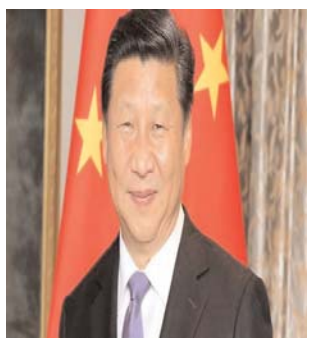

ब्रिटेन में हुआ भयंकर विस्फोट, 6 लोग घायल

लंदन, (**आरएनएस**)। ब्रिटेन के लीसेस्टर में रविवार रात को जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें एक दुकान में आग लग गई। इस हादसे में छह लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यह विस्फोट लीसेस्टर के हिंकले रोड क्षेत्र में हुआ, जिसे पुलिस ने एक 'बड़ी घटना' करार दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना का आतंकवादियों से संबंध होने के कोई संकेत नहीं हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ लीसेस्टर के मुताबिक छह घायलों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। कार्लिस्ले स्ट्रीट और हिंकले रोड स्ट्रीट को बंद कर दिया गया है और लोगों को उस क्षेत्र में नहीं जाने की हिदायत दी जा रही है। कई जगह बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। जिस जगह विस्फोट हुआ, उसके ठीक सामने रह रही महिला एंजेल नामला ने बताया कि उसने एक बड़े धमाके की आवाज सुनी...जैसे भूकंप आ गया हो। देखते ही देखते इमारत ढह गई और लोग मदद की कोशिश करने लगे लेकिन आग बढ़ती जा रही थी इसलिए लोगों को उस जगह से जाने के लिए कहा गया। वहीं स्थानीय पुलिस के मुताबिक, पुलिस और लीसेस्टर अग्नि और बचाव सेवा, दोनों मिलकर इस धमाके की जांच कर रहे हैं। घटनास्थल पर दमकल विभाग के छह वाहनों को भेजा गया। साथ ही बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है।

उत्तर कोरिया से बातचीत की शर्तें कम करे अमेरिका

सोल (**आरएनएस**)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आज कहा कि अमेरिका को उत्तर कोरिया के साथ बातचीत की शर्तों को कम करना चाहिए और दोनों देशों को जल्द ही बातचीत शुरू करनी चाहिए। राष्ट्रपति मून जेइ इन ने यह बात चीन के उपप्रधानमंत्री लीयू यांडॉन्ग के साथ बैठक में की। बता दें कि इससे एक दिन पहले उत्तर कोरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मून से कहा था कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार है। अधिकारी प्योंगचांग विंटर ओलंपिक के समापन के मौके पर कल दक्षिण कोरिया में थे। खबरों के मुताबिक, मून ने अमेरिका- उत्तर कोरिया के बीच बातचीत के लिए चीन का समर्थन मांगा तो यांडॉन्ग ने चीन द्वारा मदद करने की बात कही। मून ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बनाना बंद करना होगा, जिसके लिए वह बार-बाक इनकार करता है। इससे पहले, अमेरिका ने कहा था कि उत्तर कोरिया जब तक अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ नहीं देता है तब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उसपर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाए रखने की जरूरत है।

कानूनी शिकंजे में पूर्व प्रधानमंत्री

ढाका ,(**आरएनएस**)। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह 24 अप्रैल तक खालिदा जिया और बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी के 48 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाले और तुरंत ऐक्शन ले।खालिदा और बाकी 48 नेता 2015 में हुए एक मामले में संलिप्त पाए गए जिसमें एक बस में आग लगने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई थी। कोमिला अदालत के अपर न्यायाधीश जोयनब बेगम ने यह आदेश दिया और सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की। ढाका ट्रिब्यून को पुलिस इंस्पेक्टर सुब्रता बनर्जी ने बताया, अदालत ने 2 जनवरी को 69 लोगों कि खिलाफ चार्जशीट स्वीकार की। चूंकि वे लोग अदालत में पेश नहीं हुए तो बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी की मुखिया खालिदा जिया और बाकी लोगों के खिलाफ वांरट जारी किया गया। बता दें कि 2015 में एक सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक यात्री बस में आगजनी की गई थी जिसमें 8 लोग मारे गए थे और 20 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 2 अलग-अलग केस दर्ज किए गए थे। खालिदा जिया समेत 77 लोगों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया था। 2 बार रहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं।

रक्षा मंत्री खरीदते रहे मच्छी, हो गया सौदा

सौंदत्ती (**आरएनएस**)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। लंबे समय से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट डील पर सरकार को घेर रहे राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कर्नाटक के सौंदत्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राफेल सौदे में पीएम ने रक्षा मंत्री तक से चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री गोवा में थे, मछली की दुकान में मछली खरीद रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि मोदी जी ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। गौरतलब है कि लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण से पहले भी कांग्रेस ने राफेल डील के बारे में सवाल किया था। राहुल यहीं नहीं रुके और बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले का भी सवाल उठाया। उन्होंने बीजेपी पर व्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम करके बीजेपी के लोगों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के साथ मिलकर येलम्मा मंदिर में पारंपरिक वाद्य भी बजाया। हाल ही में राहुल कलबुर्गी में शरणाबसप्पा मंदिर और ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह भी गए थे

राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती दुनिया की कोई ताकत

बाराबंकी (**आरएनएस**)। भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा है कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि कुछ भी हो, राम मंदिर उसी स्थान पर बनेगा, जहां रामलला विराजमान हैं. उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. कटियार ने रविवार (25 फरवरी) श,ाम यहां संवाददाता सम्मेलन में राम मंदिर के सवाल पर कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. हम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए, हर हालत में राम मंदिर वहीं बनेगा.उन्होंने कहा कि जहां भगवान स्थापित हैं वह वहीं विराजमान रहेंगे. वह भूमि भगवान राम की है और कोई ताकत वहां मंदिर बनने से नहीं रोक सकती. कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर देश और प्रदेश के लिए सजगता से काम कर रहे हैं.सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राम मंदिर-बाबरी मस्जिद पूरी तरह भूमि विवाद सर्वोच्च न्यायालय ने बीते 8 फरवरी को कहा था कि वह राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले को पूरी तरह से भूमि विवाद मानकर सुनवाई करेगा और उसने दैनिक आधार पर सुनवाई करने से मना कर दिया. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने याचिककर्ताओं की रोजाना सुनवाई करने की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया, 700 से ज्यादा गरीब वादी न्याय पाने का इंतजार कर रहे हैं, हमें उन्हें सुनना होगा. सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च तय करते हुए न्यायालय ने पार्टियों से इसके पहले इस मामले में दस्तावेजों की अनूदित प्रतियां दाखिल करने के लिए कहा था. न्यायालय 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसने विवादित बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि स्थल को निर्मोही अखाड़ा, भगवान राम की जहां मूर्ति है, उसे रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बांटने का फैसला दिया था. उच्च न्यायालय के इस फैसले को याचिकाकर्ताओं एम. सिद्दीकी के कानूनी उत्तराधिकारियों, निर्मोही अखाड़ा, उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, भगवान श्री राम विराजमान, अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणि, अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारतीय श्री रामजन्म भूमि पुनरुद्धार समिति और अन्य ने चुनौती दी थी.

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र रायगढ़ एवं जशपुर जिले हेतु रिपोर्टर/संवाददाता चाहिए तत्काल संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9589876400

C M Y K